आई॰सी॰डी॰एस॰ परियोजनाओं की संक्रिया

1390. **श्री महेश्वर सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) देश में कुल कितने विकास खंडों में इस समय आई॰सी॰डी॰एस॰ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) हिमाचल प्रदेश में कुल कितने विकास खंड हैं और कुल कितने खंड़ों में ये परियोजनाएं कब से चलाई जा रही हैं;

(ग) आई॰सी॰डी॰एस॰ केन्द्र खोलने हेतु कौन-कौन से मानदंड हैं और क्या पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के केन्द्र खोलने हेतु जनसंख्या के मापदंड में कोई छूट दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई): (क) इन दिनों कुल 3005 सामुदायिक विकास खंडों में चालू आई सी डी एस परियोजनाएं हैं। इन चालू आई सी डी एस परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है। **(नीचे देखिए)**

(ख) हिमाचल प्रदेश में 71 सामुदायिक विकास खंड हैं, जिनमें से 41 खंडों में इन दिनों चालू आई सी डी एस परियोजनाएं हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार ये चालू आई सी डी एस परियोजनाएं वर्ष 1975-76 से 1993-94 के दौरान स्वीकृत की गयी थीं।

(ग) और (घ) औसतन, ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या के लिये तथा आदिवासी क्षेत्रों में 700 व्यक्तियों के लिये एक आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया जाता है। तथापि, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में मापदंड में छूट है जहां बस्तियां/ग्राम दूर-दूर बसे हैं और वहां के निवासी बहुत थोड़े हैं। ऐसे क्षेत्रों में 300 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव अथवा बस्ती में एक आंगनवाड़ी स्थापित की जा सकती है।

विवरण

ऐसे सामुदायिक विकास खंडों की राज्यवार संख्या जहां इन दिनों आई सी डी एस परियोजनाएं चालू हैं।

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऐसे सामुदायिक विकास खंडों की संख्या जहां इन दिनों आई॰सी॰डी॰एस परियोजनाएं चालू हैं।
1.	आन्ध्र प्रदेश	158
2.	अरूणाचल प्रदेश	38
3	असम	68
4.	बिहार	235
5.	गोवा	11
6.	गुजरात	121
7.	हरियाणा	92
8.	हिमाचल प्रदेश	41
9.	जम्मू कश्मीर	65
10.	कर्नाटक	164
11.	केरल	102
12.	मध्य प्रदेश	260
13.	महाराष्ट्र	152
14.	मणिपुर	24
15.	मेघालय	30
16.	मिजोरम	20
17.	नागालैंड	26
18.	उड़ीसा	213

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऐसे सामुदायिक विकास खंडों की संख्या जहां इन दिनों आईसीडीएस परियोजनाएं चालू हैं।
19.	पंजाब	63
20.	राजस्थान	147
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	386
23.	त्रिपुरा	18
24.	उत्तर प्रदेश	361
25.	प० बंगाल	192
26.	अंडमान और निकोबार	द्वीप समूह
27.	चंडीगढ़	0
28.	दादरा और नगर हवेली	1
29.	दिल्ली	3
30.	दमन और द्वीव	2
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	3
	योग:	3005

Hike in Prices of Milk

1391. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) whether there was a steep hike in the prices of tonned milk being supplied by the Mother Dairy recently as compared to the prices of DMS;

(b) if so, the extent of hike made in the prices thereof alongwith the reasons therefor;

(c) the number of times, the prices were hiked by the Mother Dairy as compared to DMS during the last one year indicating the extent of hike made by both of them in the prices each time; and

(d) whether Government propose to provide more subsidy to Delhi Government and other State Governments particularly Rajasthan, so that some check on rising prices of milk could be maintained?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. RAGKUVANSH PRASAD SINGH): (a) and (b) The Mother Dairy, Delhi has revised the price of toned milk w.e.f. 8-5-1996 as under:—

	From	To
through bulk	Rs. 9/- ltr.	Rs. 11/- ltr.
vending in polypack	Rs. 10/- ltr.	Rs. 12/- ltr.

The price was revised in order to cope up with enhanced procurement prices paid to farmers for raw milk and thereby maintain viability of operations. The price of toned milk in polypacks sold by DMS is Rs. 7/- ltr.

(c) There was no increase in the price of milk sold by DMS after September, 1992. The immediate previous price revision by Mother Dairy was effected in May 1995.

(d) No Sir.